



भारत का राजपत्र

The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 197]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 6, 2011/चैत्र 16, 1933

No. 197]

NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 6, 2011/CHAITRA 16, 1933

ग्रामीण विकास मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 अप्रैल, 2011

सा.का.नि. 307(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 (2005 का केन्द्रीय अधिनियम 42) की धारा 24 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के परामर्श से प्रस्तावित क्रतिपय नियमों के निम्नलिखित प्रारूप को उक्त अधिनियम की धारा 32 की उप-धारा (1) में अपेक्षानुसार इनसे प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है और सूचित किया जाता है कि राजपत्र, जिसमें इस अधिसूचना को प्रकाशित किया गया है, की प्रतियां जनता को उपलब्ध कराने की तारीख से तीस दिन की अवधि के समाप्त होने के पश्चात् उक्त प्रारूप नियमों पर विचार किया जाएगा;

उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर किसी व्यक्ति से प्राप्त आक्षेपों या सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

आक्षेपों और आपत्तियों, यदि कोई हों, को अवर सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार, कमरा नं. 366-ए, कृषि भवन, डा. राजेन्द्र प्रसाद मार्ग, नई दिल्ली- 110001 (दूरभाष-23073787, फैक्स- 23388431, ई मेल: rk.sood@nic.in) को भेजा जा सकेगा।

प्रारूप नियम

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.—(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीमों की लेखा-परीक्षा नियम, 2011 है।

(2) ये राजपत्र में अंतिम प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. लेखों की लेखा-परीक्षा.—अधिनियम के अधीन प्रत्येक जिले के लिए प्रत्येक वर्ष की स्कीम के लेखों की लेखा-परीक्षा, या तो निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा अथवा समकक्ष प्राधिकारी या भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के पास सूचीबद्ध चार्टड एकाउटैट या चार्टड एकाउटैट फर्मों की सूची में से राज्य सरकार द्वारा नियुक्त चार्टड एकाउटैट द्वारा की जाएगी और भारत के

नियंत्रक और महालेखाकार द्वारा समय-समय पर चार्टड एकाउंटेंट के चयन और उनकी नियुक्ति के लिए मानदंड और शर्तें विनिर्दिष्ट की जाएंगी ।

(2) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक लेखा-परीक्षा किए जाने और उस पर लेखा-परीक्षा रिपोर्ट के प्ररूप, संरचना एवं विषयवस्तु से संबंधित चार्टड एकाउंटेंट को निदेश एवं अनुदेश जारी करेगा ।

(3) यथास्थिति, चार्टड एकाउंटेंट अथवा निदेशक, स्थानीय निधि लेखा-परीक्षा द्वारा लेखा-परीक्षा रिपोर्ट की प्रतियां राज्य सरकार को प्रस्तुत की जाएंगी और राज्य महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) ऐसी लेखा-परीक्षा रिपोर्टों पर टिप्पणी कर सकेगा ।

(4) भारत का नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा उसके द्वारा इस निमित नियुक्ति किसी व्यक्ति को स्कीमों के लेखों की ऐसी अवधि पर जो वह ठीक समझे, लेखा-परीक्षा करने का अधिकार होगा ।

3. सामाजिक लेखा-परीक्षा सुविधा—(1) राज्य सरकार, महात्मा गांधी नरेंगों के अधीन स्कीमों की लेखा-परीक्षा निदेशालय (जिसे इसमें इसके पश्चात लेखा-परीक्षा निदेशालय कहा गया है) की स्थापना करेगी जिसमें संपूर्ण राज्य में सामाजिक लेखा-परीक्षा सहित लेखों की लेखा-परीक्षा संबंधी प्रक्रिया को सुकर बनाया जा सके और उसकी जांच की जा सके और इसके द्वारा नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक और राज्य महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) के बीच समन्वयक का कार्य किया जा सके ।

(2) लेखा-परीक्षा निदेशालय द्वारा समुदाय तथा अन्य सिविल सोसायटी संगठनों से जिला और राज्य स्तर पर ऐसे संसाधन व्यक्तियों का चयन किया जाएगा जो आधारभूत स्तर पर लोगों को अधिकार-संपन्न बनाने और उन्हें सुदृढ़ करने तथा सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रक्रियाओं में प्रशिक्षण देने, दस्तावेजों की संवीक्षा और विश्लेषण, स्थलों या सामग्री के स्टॉक के सत्यापन, रिपोर्ट तैयार करने, सामाजिक लेखा-परीक्षा की कार्यवाहियों को अभिलिखित करने संबंधी जानकारी एवं अनुभव रखते हों ।

(3) लेखा-परीक्षा निदेशालय, राज्य में कार्यान्वित की जाने वाली प्रत्येक स्कीम की अपेक्षाओं की समीक्षा करने के लिए सुविधादाता का भी कार्य करेगा, कर्मियों की हकदारी संबंधी अपेक्षाओं का

अनुमान तैयार करेगा, आधारभूत स्तर पर निधियों के समुचित उपयोग की निगरानी करेगा और निम्नलिखित की व्यवस्था भी करेगा अर्थात् :-

(क) सतत रूप से सामाजिक लेखा-परीक्षा करने के लिए ग्रामीण समुदाय की क्षमता का निर्माण करना;

(ख) पारदर्शिता तथा जवाबदेही सुकर बनाने के लिए सतर्कता, निगरानी तथा अन्य सम्बद्ध कार्यकलाप निष्पादित करना;

(ग) सामाजिक लेखा-परीक्षा प्रक्रिया के संबंध में संसाधन सामग्री, दिशानिर्देशों एवं नियम पुस्तिका की व्यवस्था करना;

(घ) सामाजिक लेखा-परीक्षा समिति के सदस्यों को संसाधन व्यक्तियों के माध्यम से प्रशिक्षण देना;

(4) लेखा-परीक्षा निदेशालय, सामाजिक लेखा-परीक्षा के संबंध में राज्य सरकार द्वारा की गई कार्रवाई की निगरानी करेगा और जानकारी को सार्वजनिक रूप से उपलब्ध कराएगा ;

(5) लेखा-परीक्षा निदेशालय की स्थापना संबंधी लागत की, केन्द्रीय सरकार द्वारा भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार केन्द्रीय सहायता के रूप में पूर्ति की जाएगी ।

4. सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया - (1) सामाजिक लेखा परीक्षा, स्कीम को क्रियान्वित करने वाली किसी भी अभिकरण द्वारा की गई प्रक्रिया से स्वतंत्र प्रक्रिया होगी ।

(2) कार्यान्वयन अभिकरण, किसी भी समय अर्थात् सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के पूर्व, दौरान या पश्चात्, सामाजिक लेखा परीक्षा में हस्तक्षेप नहीं करेगा ।

(3) उप-नियम (2) में किसी भी बात के होते हुए भी, स्कीम को कार्यान्वित करने वाला अभिकरण, सामाजिक लेखा परीक्षा कराने के लिए लेखा परीक्षा निदेशालय को अपेक्षित जानकारी उपलब्ध कराएगा ।

5. सामाजिक लेखा परीक्षा करने की प्रक्रिया - (1) लेखा परीक्षा निदेशालय प्रत्येक छह मास में कम से कम एक लेखा परीक्षा करने के लिए वार्षिक कैलेण्डर तैयार करेगा और इस कैलेण्डर की एक प्रति सभी जिला कार्यक्रम समन्वयकों और राज्य महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को सूचनार्थ

एवं आवश्यक प्रबंध करने के लिए भेजी जाएगी ।

(2) लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा प्रशिक्षित किए गए सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्ति अपनी स्वयं की ग्राम पंचायतों से भिन्न ग्राम पंचायतों में लेखा परीक्षा निदेशालय के प्रतिनिधियों के साथ सामाजिक लेखा परीक्षा सुकर करेंगे । संसाधन व्यक्तियों की लेखा परीक्षा रिपोर्ट के प्ररूप लेखा परीक्षा निदेशालय द्वारा विनिर्दिष्ट किए जा सकेंगे ।

(3) सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा, पारदर्शिता और जवाबदेही की विद्यमान अपेक्षाओं के अनुपालन की समीक्षा, श्रमिकों की हकदारियों की पूर्ति (बेरोजगारी भत्ते का भुगतान सहित) तथा जमीनी स्तर पर निधियों का समुचित उपयोग करने का अवसर प्रदान करेगी और साथ ही उनके क्षेत्रों में अधिनियम के अधीन कार्यान्वयन की गई सभी स्कीमों की विस्तृत सार्वजनिक लेखा परीक्षा कराने के लिए संस्थागत ग्राम सभा के रूप में भी कार्य करेगी ।

(4) यह सुनिश्चित करने की जिम्मेदारी, कार्यक्रम अधिकारी की होगी कि सभी अपेक्षित जानकारियां और रिकार्ड उचित रूप से अपेक्षित प्ररूप में संग्रहीत किए जाते हैं और सभी संबंधित रिकार्डों की फोटो प्रतियों के साथ सामाजिक लेखा परीक्षा कराने वाली ग्राम सभा और सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्तियों को सामाजिक लेखा परीक्षा कराने वाली ग्राम सभा की बैठक की निर्धारित तारीख से कम से कम पन्द्रह दिन पूर्व उपलब्ध कराए जाते हैं । उसी समय यह जानकारी सार्वजनिक रूप से भी उपलब्ध होनी चाहिए तथा नाममात्र कीमत पर इनकी फोटोप्रतियां उपलब्ध होनी चाहिए ।

(5) अधिनियम के अधीन स्कीमों के कार्यान्वयन में समिलित सभी जन प्रतिनिधि और कर्मचारीवृद्ध (गैर सरकारी संगठनों, स्व-सहायता समूहों आदि के कर्मचारीवृद्धों सहित, यदि कोई स्कीमों के क्रियान्वयन में समिलित है) ग्राम सभा में प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उपस्थित रहेंगे । ग्राम सभा संसाधन व्यक्तियों, जनप्रतिनिधियों और सरकारी कर्मचारियों से और अधिक जानकारी प्राप्त करने तथा प्रश्नों का उत्तर जानने की दृष्टि से सभी ग्रामीणों को एक मंच उपलब्ध कराएगी ।

(6) नियंत्रक और महालेखापरीक्षक द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति, सामाजिक लेखा परीक्षा कराने वाली ग्राम सभा में उपस्थित रह सकेगा और ग्राम सभा में स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में जानकारी और स्पष्टीकरण (लेखा परीक्षा के ब्यौरे और टिप्पणियों सहित) उपलब्ध करा सकेगा । तथा वह सामाजिक लेखा परीक्षा की प्रक्रिया को सुकर भी कर सकेगा ।

(7) सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा, व्यापक जन भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए एक खुली एवं समावेशी ग्राम सभा होगी ।

(8) सामाजिक लेखा परीक्षा करने वाली ग्राम सभा की अध्यक्षता उस व्यक्ति के द्वारा की जाएगी जो प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से इस अधिनियम के अधीन स्कीम के कार्यान्वयन में सम्मिलित नहीं हैं ।

(9) जिला कार्यक्रम समन्वयक, सामाजिक लेखा परीक्षा ग्राम सभा की बैठक में भाग लेने के लिए उपयुक्त स्तर के पदधारी को नामनिर्दिष्ट करेंगे और ऐसा अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि ग्राम सभा की बैठक एक जनतांत्रिक स्वरूप में ऐसे वातावरण में होती है जहां प्रत्येक व्यक्ति निर्भीक होकर बोल सकते हैं और साक्ष्य दे सकते हैं । अधिकारी, निर्धारित प्रपत्र के अनुसार जिला कार्यक्रम समन्वयक के पास रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए जिम्मेदार है ।

(10) स्थानीय भाषा में सामाजिक लेखा परीक्षा रिपोर्ट, ग्राम पंचायत के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित की जाएगी और इन रिपोर्टों पर की गई कार्रवाई की नियमित अद्यतन भी किया जाएगा और उसे सूचना पट्ट पर प्रदर्शित किया जाएगा । अनियमितताओं में सम्मिलित पाए गए व्यक्तियों के नाम इन रिपोर्टों में उल्लिखित किए जाएंगे और उनके विरुद्ध की गई अथवा की जा रही कार्रवाई स्पष्ट रूप से दर्शाई जाएगी ।

(11) पूर्व सामाजिक लेखा परीक्षा से संबंधित की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रत्येक सामाजिक लेखा परीक्षा के बैठक के आरंभ में पढ़कर सुनाई जाएगी ।

(12) सामाजिक लेखा परीक्षा आयोजित किए जाने के एक मास के भीतर संबंधित प्राधिकारी द्वारा लेखा परीक्षा निदेशालय के पास की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की जाएंगी ।

6. लेखा परीक्षा के संबंध में कतिपय व्यक्तियों की बाध्यता : प्रत्येक जिला कार्यक्रम समन्वयक अथवा उनकी ओर से कोई पदधारी निम्नलिखित कार्य करेंगे :

(क) यथा संभव, सामाजिक लेखा परीक्षा की आम बैठक में भाग लेंगे;

(ख) यह सुनिश्चित करेंगे कि सामाजिक लेखा परीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई की गई है;

(ग) इस अधिनियम के प्रयोजन से भिन्न प्राप्त अथवा उपयोग की गई अथवा गबन की गई धनराशि की वसूली के लिए उपाय करना;

(घ) खंड (ग) के अधीन प्राप्त धनराशि के लिए प्राप्ति अथवा स्वीकृति पत्र जारी करना;

(ङ) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन मजदूरी की मांग करने वाले व्यक्तियों को देय मजदूरी के लिए धनराशि की प्राप्ति के सात दिनों के भीतर भुगतान करेंगे;

(च) महात्मा गांधी एनआरईजीएस लेखा में पृथक शीर्ष के अधीन सामाजिक लेखा परीक्षा प्रक्रिया के दौरान वसूल की गई धनराशि के संबंध में प्रविष्टि को अभिलिखित करेंगे;

(छ) : यह सुनिश्चित करेंगे कि यदि कोई व्यष्टि अथवा व्यष्टियों या व्यक्तियों समूह इस अधिनियम के अधीन स्कीमों के लिए निर्धारित की गई राशि को अधिनियम के प्रयोजनों से भिन्न

किसी अन्य प्रयोजन के लिए प्राप्त करता है अथवा उसका उपयोग करता है अथवा गबन करता है, तो उसके विरुद्ध उपयुक्त कार्यवाई (दाप्तिक और सिविल कार्यवाही करने अथवा संबंधित कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने सहित) की गई हैं।

7. **सामाजिक लेखा परीक्षा का विस्तार और समावेशन** - ग्राम सभा तथा सामाजिक लेखा परीक्षा को सुकर करने वाले संसाधन व्यक्ति को स्कीमों के कार्यान्वयन के संबंध में पुस्तकें, खाते, संबंधित वाउचर तथा अन्य दस्तावेज तथा कागजात की मांग करने का अधिकार होगा।

(2) सामाजिक लेखा परीक्षा करते समय ग्राम सभा तथा संसाधन व्यक्ति अपने समक्ष प्रस्तुत किए गए अन्य सभी सार्वान अभिलेखों सहित निम्न का सत्यापन करेंगे -

(i) मस्टर रोल, यदि आवश्यक हो, तो ऐसे मास्टर रोल में जिन मजदूरी मांगने वालों के नाम प्रविष्ट किए गए हैं उनसे संपर्क करके निर्धारित समयावधि में की गई प्रविष्टि तथा भुगतान;

(ii) कार्यस्थल तथा किए गए कार्य की मात्रा और गुणवत्ता का निर्धारण करना;

(iii) वित्तीय जानकारी की सत्यता एवं विश्वसनीयता का सत्यापन करने के लिए रोकड़बही, बैंक विवरण तथा अन्य वित्तीय अभिलेख;

(iv) सामग्रियों की खरीद के लिए उपयोग किए गए बीजक, बिल, वाउचर अथवा अन्य संबंधित अभिलेख जिसमें यह पता लगाया जा सके कि किफायती दर पर खरीद की गई थी तथा उसका पूरा उपयोग किया गया था इत्यादि।

(3) सामाजिक लेखा परीक्षा संसाधन व्यक्तियों तथा प्रशासन कामगारों तथा ग्रामीण समुदाय को ग्राम सभा द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा किए जाने की जानकारी देंगे जिससे उनकी पूर्ण भागीदारी हो सके; कामगारों को अधिनियम के अधीन उनके अधिकारों और हकदारी के बारे में जागरूक बनाया जा सके तथा यह सामाजिक लेखा परीक्षा को सुकर बनाने का एक महत्वपूर्ण भाग होगा।

(4) नियंत्रक और महालेखा परीक्षक अथवा इस निमित्त उसके द्वारा नियुक्त किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्रमाणित किए गए प्रत्येक राज्य सरकार की स्कीमों के लेखाओं तथा उसकी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, दोनों को प्रत्येक वर्ष केंद्रीय सरकार को भेजा जाएगा।

(5) केंद्रीय सरकार, लेखा परीक्षा रिपोर्ट तथा वार्षिक रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् उन्हें संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष प्रस्तुत करेगी।

MINISTRY OF RURAL DEVELOPMENT

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th April, 2011

G.S.R. 307(E).—The following draft of certain rules which the Central Government, in consultation with the Comptroller and Auditor General of India, proposes to make in exercise of the powers conferred by the sub-section (1) of section 24 of the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Act, 2005 (Central Act 42 of 2005), is hereby published as required by sub-section (1) of section 32 of the said Act, for information of all persons likely to be affected thereby and notice is hereby given that the said draft rules will be taken into consideration after the expiry of a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, which may be received from any person in respect of the said draft rules within the period specified above, will be ~~considered~~ by the Central Government;

The objections and suggestions, if any, may be addressed to the Under Secretary, Ministry of Rural Development, Government of India, Room No. 366-A, Krishi Bhawan, Dr. Rajendra Prasad Marg, New Delhi-110001 (Tel. 23073787, Fax 23388431, E-mail rk.sood@nic.in).

DRAFT RULES

1. Short title and commencement.— (1) These rules may be called the Mahatma Gandhi National Rural Employment Guarantee Audits of Schemes Rules, 2011.

(2) They shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. Audit of accounts.—The audit of the accounts of a Scheme under the Act for each district for each year shall be carried out by either by the Director, Local Fund Audit or equivalent authority or by Chartered Accountants to be appointed by the State Government from amongst the list of Chartered Accountants or Chartered Accountant firms empanelled with the Comptroller and Auditor General of India and the Controller Auditor General of India may specify from time to time

such criteria and terms and conditions for selection and appointment of the Chartered Accountants.

(2) The Comptroller and Auditor General of India shall issue directions and instructions to the Chartered Accountants regarding the conduct of audit and the format, structure and contents of the audit report thereon.

(3) The Chartered Accountant or the Director, Local Fund Audit, as the case may be, shall submit copies of the Audit Report to the State Government and the State Accountant General (Audit), may comment upon such Audit Report.

(4) The Comptroller and Auditor General of India or any person appointed by him in this behalf shall have the right to conduct audit of the accounts of Schemes at such frequency as they may deem fit.

3. Social audit facilitation.—(1) The State Government shall establish a Directorate of Audit of Schemes under MGNREGA (hereinafter referred to as the Directorate of Audit) to facilitate and oversee the process of audit of accounts including the social audits throughout the State and act as a co-ordinator between the Comptroller and Auditor General and State Accountant General (Audit).

(2) The Directorate of Audit shall select the resource persons from community and other civil-society organisations at district level and at State level who are having knowledge and experience of working on strengthening and establishing the rights of people at the grassroots and provide training in social audit processes, scrutiny and analysis of documents, physical verification of sites or stock of materials, preparation of reports, recording of proceedings of social audit.

(3) The Directorate of Audit also function as facilitator to review ongoing requirements of each Scheme implemented in the State, prepares estimates of required entitlements of workers, monitors proper utilization of funds at grassroots and also provided the following, namely:—

(a) capacity building of village community to conduct continuous social audit;
(b) vigilance, monitoring and other associated activities which facilitate transparency and accountability;
(c) resource material, guidelines and manuals in respect of the social audit process;
(d) impart training to the members of the Social Audit Committee by the resource persons;

(4) The Directorate of Audit shall monitor the action taken by the State Government on Social Audit and shall host the information in the public domain.

(5) The costs of establishing the Directorate of Audit shall be met by the Central Government as a Central assistance as per Government of India guidelines.

4. Social Audit Process.—(1) The Social Audit shall be a process independent of any process undertaken by the agency implementing the Scheme.

(2) The implementing agency at no time, whether prior to, during or after the conduct of social audit, interfere with the Social Audit.

(3) Notwithstanding anything contained in sub-rule (2), the agency implementing the Scheme shall provide requisite information to the Directorate of Audit conducting the Social Audit.

5. Procedure for conducting Social Audit.—(1) The Directorate of Audit shall frame an annual calendar to conduct at least one audit in every six months and a copy of the calendar shall be sent to all the District Programme Coordinators and to the State Accountant General (Audit) for information and necessary arrangements.

(2) The social audit resource persons trained by the Directorate of Audit shall facilitate the social audit along with the representatives of the Directorate of Audit in Gram Panchayats other than their own Gram Panchayats. The formats for the audit report of the resource persons may be specified by the Directorate of Audit.

(3) Social Audit Gram Sabha will provide an opportunity to review compliance with ongoing requirements of transparency and accountability, fulfillment of the entitlements of labourers (including payment of unemployment allowance), and proper utilisation of funds at the grassroots level, as well as serving as an institutional Gram Sabha for conduct of a detailed public audit of all Schemes under the Act that have been carried out in their area.

(4) It shall be the responsibility of the Programme Officer to ensure that all the required information and records are properly collated in the requisite formats and provided, along with photocopies of all related records, to the Gram Sabha conducting social audit and Social Audit resource person at least fifteen days in advance of the scheduled date of meeting of the Gram Sabha conducting social audit. This information should also be publicly available at the same time, and photocopies available at nominal cost.

(5) All public representatives and staff involved in implementing the Schemes under the Act (including the staff of the Non-Governmental Organisations the Self Help Groups, etc., if any, involved in implementing Schemes shall be present at the Gram Sabha to respond to queries. The Gram Sabha will provide a platform to all villagers to seek and obtain further information and responses from the resource persons, public representatives and officials.

(6) The person appointed by the Comptroller and Auditor General may be present at the Gram Sabha conducting social audit and may provide information and clarifications (including details of audit findings and observations) relating to the implementation of the Schemes at the Gram Sabha and he may also facilitate the social audit process.

(7) The Social Audit Gram Sabha shall be an open and inclusive Gram Sabha to encourage broad based public participation.

(8) The Gram Sabha conducting the Social Audit shall be presided over by a person, who is not directly or indirectly, involved in implementation of the Scheme under the Act.

(9) District Programme Co-ordinator shall nominate an official of an appropriate level to attend the Social Audit Gram Sabha meeting and such officer may ensure that the Gram Sabha takes place in true democratic spirit in an atmosphere where everyone can speak and testify without fear. The officer will be responsible for filing a report with the District Programme Coordinator, as per the prescribed format.

(10) The Social Audit Reports in the local language shall be posted on the notice board of the Gram Panchayat, and action taken on these Reports shall also be updated and indicated regularly on the notice boards. Persons found involved in irregularities shall be named in these reports, and action taken or under process against them clearly indicated.

(11) The action taken report relating to the previous social audit shall be read out at the beginning of the meeting of each social audit.

(12) All action taken reports shall be filed by the concerned authority within a month of convening of the social audit to the Directorate of Audit.

6. Obligation of certain persons in relation to Audit. – Every District Programme Coordinator or any Official on his behalf, shall, -

- (a) as far as possible, attend the Social Audit Public Meetings;
- (b) ensure corrective action is taken on the Social Audit findings;
- (c) take steps to recover the moneys, received or used other than the purpose of the Act, or, embezzled;
- (d) issue receipts or acknowledgement for moneys received under clause (c);
- (e) pay, within seven days of the receipt of the money for the wages due to the wage seekers under the provisions of this Act;
- (f) record the entry in respect of the money recovered during the Social Audit process under a separate head in the Mahatma Gandhi NREGS account;
- (g) ensure that the appropriate action (including initiating criminal and civil proceedings or

termination of services of the concerned employees) is initiated against any individual or class of individuals or persons who received or used other than the purposes of the Act or embezzled the moneys meant for the Schemes under the Act.”

7. Scope and Coverage of Social Audit.—The Gram Sabha and the resource persons facilitating the social audit shall have the right to demand the production of books, accounts, connected vouchers and other documents and papers in connection with the implementation of the Schemes.

(2) While conducting the social audit, along with all other material records placed before them, the Gram Sabha and the resource person shall verify,—

- (i) the muster rolls, entry and payments made in the time period specified, if necessary by contacting the wage seekers whose names are entered in such muster rolls;
- (ii) the work site and assess the quantity and quality of work done;
- (iii) the cash book, bank statements and other financial records to verify the correctness and reliability of financial reporting;
- (iv) the invoices, bills, vouchers or other related records used for procurement of materials to testify such procurement was economical, fully utilised, etc.

(3) The labourers and village community shall be informed about the Gram Sabha conducting Social Audit by the social audit resource persons as well as the Administration to ensure full participation. Creating awareness amongst the labourers about their rights and entitlements under the Act will be an important part of the Social Audit Facilitation.

(4) The accounts of the Schemes of every State Government as certified by the Comptroller and Auditor General or any other person appointed by him in this behalf together with the audit report thereon shall be forwarded annually to the Central Government.

(5) The Central Government shall cause the audit report and the annual report to be laid, as soon as may be after they are received, before each House of Parliament.

[F. No. K-11033/50/2010-MGNREGA]

AMITA SHARMA, Jt. Secy.